ऊपर वहां की स्थानीय भाषाओं के अंदर प्रसारण होता है। कुछ प्रान्तों में उससे अधिक भी होता है। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में जिनका फैलाव बाहर तक भी है 24 घंटे के क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल भी हैं। जहां तक हिन्दी भाषी प्रान्तों का संबंध है वहां पर जो प्रसारण नेशनल चैनल के ऊपर होता है उसका समय आजकल ढाई घंटे के करीब है। हिमाचल प्रदेश में शिमला दूरदर्शन केन्द्र है लेकिन वहां पर उसका प्रसारण अभी तक लगभग आधा घंटे के करीब हो रहा है। कभी कभी एक घंटा भी होता है। मैं कुछ सप्ताह पहले हिमाचल प्रदेश गया था। वहां पर लोगों ने भी प्रस्ताव रखा कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूं और यह सुझाव मैंने प्रसार भारती के अधिकारियों को पहुंचा दिया है।

श्री सुरेश पचौरी: माननीय मंत्री जी सदन की घड़ी के अनुसार उत्तर नहीं दे रहे हैं। सदन की घड़ी में अभी 11 नहीं बजे हैं।

श्री सभापति: सदन की घड़ियां ठप हो गई हैं। सारी बिल्डिंग की घड़ियां बंद हो गई हैं। समय बंद नहीं हुआ है, समय चल रहा है।

Contract for development of Ratna and R-Series discovered oil fields

*102. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contract for the development of Ratna and R-Series discovered oil fields was awarded in favour of consortium of Essar Oil Ltd., Premier Oil Ltd. and ONGC in November, 1996;

(b) whether it is also a fact that no progress has been made towards the finalisation of Production Sharing Contract with this consortium despite the fact that more than 3½ years have passed since the award of contract;

(c) if so, the reason therefor;

(d) whether Government propose to cancel this award; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK) (a) The Ratna and R-Series field was awarded to the consortium of Essar Oil Ltd. and Preimier Oil Plc., U.K. in March 1996. ONGC has 40% participating interest in the development of the field in accordance with the terms of Notice Inviting Offers (NIO).

(b) and (c) Due to review of the discovered field policy by the Government, the discussions on the Production Sharing Contract (PSC) started in December 1999 and thereafter sittings have been held.

(d) No, sir.

(e) The discussions on the PSC with the awardees have not been concluded.

SHRI AMAR SINGH: Sir, my first supplementary is, whether the Government is aware that production sharing contracts for Ratna and R-Series are not being finalised because the Essar Oil Ltd. is not in a position to fulfil the contractual obligations; as a result thereof, the production of crude oil remained low. Sir, due to this, the Government have been deprived of fresh foreign loan from the World Bank. Is it not the same company which was mentioned by Shri Mohan Guruswamy, the then Financial Advisor of the hon. Finance Minister in his controversial statement, alleging that the Government was always under pressure to promote crony capitalism for this company?

श्री राम नाईक: सभापति जी, यह बात सही है कि यह मामला नवम्बर, 1996 से चल रहा है और कई कारणों से इसमें विलम्ब हुआ है। एक तो प्रोडक्शन शेयरिंग की क्या पालिसी होनी चाहिये इस पर समय-समय की सरकारें विचार करती रहीं। 1996 से 1999 तक हर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार एक साल, डेढ़ साल रही और इसमें जो प्रोडक्शन शेयरिंग पालिसी तय करनी चाहिये थी इससे कुछ विलम्ब हुआ। अब यह प्रोडिक्शन शेयरिंग पालिसी तय हुई है। मैं अक्तूबर में इस विभाग का मंत्री बना तभी से क्या-क्या बैकलांग है, क्या-क्या रह गया है, मैं यह सब देख रहा हूं। इसमें प्रोडक्शन शेयरिंग का सवाल भी था जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने प्रश्न के ज़रिये किया है। उस समय पर इस प्रकार के 12 मामले थे । अब 12 मामलों में से हमने 10 मामलों के संबंध में सारी बातें तय की हैं। अब आने वाले सप्ताह में ही उसके बारे में हस्ताक्षर हो जाएंगे। केवल दो मामल रह गये हैं। उसमें से एक रत्ना फील्ड का है और एक अंगोरी आसाम में है। इन दोनों के साथ बाचीत चल रही है। अंतिम बातचीत 18 जुलाई को हुई थी और 18 जुलाई की बातचीत के बाद उनको एक पत्र लिखा गया कि अब हम इसमें अंतिम रूप में पहुंचना चाहते हैं तो 18 सितम्बर तक उनको इसके बारे में अपनी जो भूमिका है वह स्पष्ट करनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना, दोनों प्रोडक्ट शेयरिंग के संबंध में जो फील्ड्स हैं, एक रत्ना की है और जैसा मैंने कहा कि आसाम की आंगोरी की है, इसके बारे में हमने दी है।

SHRI AMAR SINGH: Sir, my second supplementary is this. What are the reasons for not considering the award that is being deliberately delayed for the last four years? Has the Government made any assessment of the loss of

production of oil on account of the inordinate delay in the finalisation of a contract with the consortium? If so, what are the details thereof? Does the Government propose to recover that loss from the consortium? If not, what are the reasons therefor?

श्री राम नाईक: सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्शन शेयरिंग की पालिसी के बारे में सरकार में चर्चा चल रही है और सरकार में चर्चा करके उसमें जो निर्णय करना चहिए था वह नहीं हुआ था। कोई दूसरे मामले आ गए थे। एक दूसरा इसी प्रकार के ग्रुप आफ कांट्रेक्ट के संबंध में सीएजी ने फिर रिमार्क्स दिए थे, फिर उसके बारे में सीबीआई ने कुछ जांच की, सीसीए की भी एक कमेटी बन गयी थी। ये मामले कोर्ट में गए। सीबीआई जांच कर रही है। इसके तहत पहले की सरकार ने पालिसी तय करने में, मैं मान रहा हूं कि इसमें देरी की। लेकिन जब ऐसा होता है और पहले लोगों ने क्यों नहीं किया, इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैंने अब इसको इस स्थिति में ला दिया है कि हम इसके अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

श्री अमर सिंह: मंत्री जी क्या चार साल में किसी ने भी काम नहीं किया अगर पालिसी गलत थी तो? अगर दूसरे कर सकते थे तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया? मेरा आपसे अनरोध है कि आईओसी से करवा लीजिए, ओएनजीसी से करवा लीजिए।

श्री राम नाईक: देरी क्यों हुई, इसका सवाल पूछा। इसका उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हकीकत है और चार साल में इस बात का फैसला न होने के कारण हम भूगर्भ से जो क्रूड और गैस निकाल सकते थे वह नहीं निकाल सके और कितना आता इसका अंदाज तो जब प्रत्यक्ष काम शुरू होगा तभी हो सकता है। इसलिए उसका रुपए में कितना नुकसान हुआ है यह कहना तो इस समय संभव नहीं है। जब वहां से उत्पादन शुरू होगा, प्रोडक्शन बाहर निकलना शुरू होगा तो पता चलेगा कि उसमें कितना लाभ हम लोगों को होगा।

श्री अमर सिंह: क्षमा करें, मोहन गुरुस्वामी के द्वारा संदर्भित ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बस हो गया। आपके चार सवाल हो गए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: What was the purpose of this arrangement? Has this purpose been fulfilled? If not, what action are you taking so that the loss of production does not continue in future?

श्री राम नाईक: एक तो इसके आगे क्या करेगा इसके संबंध में मैंने उत्तर दिया कि अब यह प्रोडक्शन शेयरिंग का प्रोटोटाइप एग्रीमेंट तय हुआ है और इसलिए पहले जो होता था कि किसी एक को अवार्ड करना है तो उसमें 15 कंडीशंस हैं, उनके बारे में नेगोशिएशंस करने पड़ते थे, अब इस

संबंध में नेगोशिएशंस नहीं करने पड़ेंगे। जो कंसोर्टियम है उसको कितना परसेंटेज रहेगा? उसमें जो अलग अलग पार्टीज हैं वे आपस में तय करें। एक गलतफहमी मैं दूर भी करना चाहता हूं कि ओएनजीसी इस कंसोर्टियम में नहीं है। कंसोर्टियम जो होता है उसमें दूसरी कंपनीज होती हैं। ओएनजीसी का इस मामले में 40 परसेंट शेयर है और इसलिए ओएनजीसी उसमें हैं। लेकिन कंसोर्टियम जो होता है वह अलग अलग कंपनियों का होता है जैसे इस संबंध में एस्सार का प्रीमियर के साथ है और दूसरी एक कंपनी रिलायंस है वह भी एक और अमेरिकन कंपनी के साथ है, ऐसे दोनों को मिलाकर कंसोर्टियम है। इसकी सारी चर्चा जो है यह दो ही लोगों के बारे में है क्योंकि यह कंट्रक्ट फाइनलाइज, मतलब कंट्रेक्ट फाइनलाइज नहीं किया है, यह दो पार्टीज के कंट्रेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया कि कोई 12 ऐसे मामले थे, तो मैं दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो ये 12 कौन कौन से हैं जिनके मामले निपट गए और दूसरी बात यह कि सबसे ज्यादा समय यह केस कहां पेंडिंग पड़ा रहा? ज्यादा से ज्यादा समय कहां पेंडिंग पड़ा रहा था और आप कब क्लियर करेंगे?

श्री राम नाईक: मैंने कुल मिलाकर 12 का उल्लेख किया। इन 12 के उल्लेख में एक आसाम को छोड़ दें तो सभी के सभी गुजरात के हैं और गुजरात में इसमें 6 स्थानों पर गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कंपनी जो है वह भी इसमें पार्टिसिपेटिंग है। ये 6 नाम आप चाहें तो मैं बता देता हूं। लेकिन सामान्यत: गुजरात के सदस्यों को वे नाम मालूम हैं। अब यह जो दस हैं आने वाले कुछ सप्ताह में उस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे और जैसे मैंने कहा कि यह जो दो बचे हुए हैं उनको 18 सितम्बर तक सभी बातों को लेकर हमारे पास आना चाहिए, इस प्रकार का एक अंतिम पत्र हमने लिखा है।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, this contract was awarded to this company after the C.C.A. approval. Then why was this matter again referred to the C.C.A. for approval, where it took three years? Can you explain the reasons?

श्री राम नाईक: मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले एक मामले में ऐसे कई कांट्रैक्ट्स थे उसमें सीएजी के कुछ आब्जैक्शंस आए हैं। बाद में उसके संबंध में सीबीआई द्वारा कुछ केसेज़ में, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हो गयी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और दूसरा मामला दाखिल हुआ है और संभवत: कल उसकी हीयरिंग होने वाली है। ये पहले की सारी बातें हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब इसमें आगे देरी नहीं होगी। वह मैं देख रहा हूं और दोनों के संबंध में मैंने कहा कि 18 सितम्बर को हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I know, the hon. Minister appreciates that the oil sector is of a strategic nature. I understand, this delay was mainly because of the financial bankruptcy of these two companies. Sir, this is a signal more to the Ministry of Disinvestment, which is treating privatisation as panacea for all ills. The same company, which was given the bail-out package for three-and-a-half years, for the steel sector, is now being given another bail-out package for the oil sector also. My specific question to the hon. Minister is whether the Government is putting any cap on the capital costs and operation costs, as per the bids for the purpose of cost recovery knowing fully well that the company's finances are not in a very sound position. Am I correct?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इसकी जानकारी मैं इस समय नहीं रख रहा हूं कि दोनों कंपनियों की विद्यमान आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि 1993 से मामला चला आया है। मैं इसमें इतना देखूंगा कि 18 सितम्बर को जब उनसे इस बारे में सब जानकारी आएगी और उसमें फाइनांशियल मामला भी होगा। अब कौन बैंकरप्ट है और कौन नहीं है इसके संबंध में मैं अपने उत्तर में कोई अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं रख सकता हूं। अखबार के जरिए जो आता है उस पर उत्तर देना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि निर्णय करके प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रैक्ट देने के पहले यह जो एक आवश्यक बात होती है कि उसमें उस कंपनी की फाइनांशियल स्टैंडिंग एज ऑन् नाउ क्या है यह देखनी चाहिए क्योंकि इसमें उनका शेयर लगभग 700 करोड़ का है। इस प्रकार से यह एक बड़ा प्रोजैक्ट बनेगा। इसलिए इस बात का भी ख्याल किया जाएगा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What about putting a cap on the capital costs?

श्री राम नाईक: देखिए, इसलिए मैंने कहा कि किसी को भी सरकारी काम देने के पहले जितनी भी फाइनांशियल बातों की आवश्यकता होती है वे सारी बातें इसमें देखी जायेंगी।

प्रो. रामगोपाल यादव: श्रीमन्, एक तरफ बॉम्बे हाई नॉर्थ में 1979 में भूगर्भ से क्रूड आयल और गैस निकालने के लिए सबमर्सिबल इंजन का प्रयोग किया था, जो फेल हो गया था और ओएनजीसी तब से स्वयं गैस लिफ्ट आप्शन का प्रयोग कर रही है। फिर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मसले में एस्सार आयल लि. कंपनी को, यह जो ओब्सीलीट टैक्नोलोजी है, जो फेल हो चुकी है वह सबमर्सिबल पंप्स की इजाजत क्यों दी जा रही है? इस पर इतने मेहरबान क्यों हैं जबकि यह फेल होनी ही है?

श्री राम नाईक: सभापति जी, जब तक उस के साथ कांट्रेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब उस समय 1995 में निर्णय किया गया कि यह कंपनी पहली है।

यह उस समय निर्णय किया गया है। अब ओ.एन.जी.सी. बॉम्बे हाई नाम की कोई चीज भूगोल में नहीं है, वहां अभी केवल मुंबई हाई है और मुबंई हाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है। वहां का प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस का विचार हम कर रहे हैं, लेकिन उस विषय और इस प्रश्न का कोई संबंध मुश्किल से आता है।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I want to put a question to the hon. Member. Now it is admitted that delay has taken place. Is the Minister contemplating to have any outer limit for concluding the entire agreement? If it is not possible for the company to do that, will they go in for some fresh options?

SHRI RAM NAIK: I would like to inform the hon. Member that 18th September is the limit. That is the "D' day, up to which we will wait. After 18th September, takng into consideration all aspects, I will take a decision. I will cross the bridge when I come to that place, i.e., on the 18th September.

PROF. M.M. AGARWAL: Mr. Chairman, Sir, does the Minister propose to prescribe any limited damages for Essar Oil Ltd., if they do not meet the promised production?

श्री राम नाईक: सभापति जी, लीक्विडिटी डैमेजेज तब होगा जब उन के साथ कांट्रैक्ट सिग्नेचर करेंगे। अभी कांट्रेक्ट ही साइन नहीं हुआ है तो कांट्रैक्ट के कौन-कौन से हिस्से हैं, यह कहना इस समय मुश्किल है।

*103. [*The Questioner (Shri K. M. Saifullah) was absent. For answer vide page 35 infra.*]

News-Items on DD-I

*104. DR. M.N. DAS: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government consider it essential to interrupt the news-item on DD-I to present stereotyped shows; and

(b) whether that time can be utilized for presenting more on national and international news?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): (a) and (b) Prasar Bharati have intimated that news bulletins are never deviated or interrupted for presenting stereotyped shows. However, in certain